



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2008/ज्येष्ठ 8, 1930

No. 298]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2008/JYAISTHA 8, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2008

सा.का.नि. 411(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 250 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (अनधिकृत निर्माण को सील करना) नियम, 2008 के नाम से जाना जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से तात्पर्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) से है;
- (ख) “परिषद्” से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् से है;
- (ग) “अनधिकृत निर्माण” से तात्पर्य किसी भवन के निर्माण अथवा किसी ऐसे कार्य के निष्पादन से है जो उक्त अधिनियम की धारा 241 में उल्लिखित स्वीकृति के बिना अथवा उसके विपरीत अथवा किसी शर्त, जिसके अधीन इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान की गई थी, का उल्लंघन करते हुए अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा उनके अन्तर्गत बनाई गई उपविधियों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभ किया गया है, अथवा किया जा रहा है अथवा पूरा किया गया है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, का अर्थ वही होगा जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

3. अनधिकृत निर्माणों को सील करने का तरीका. —

(1) अध्यक्ष अथवा इस अधिनियम की धारा 400 के अंतर्गत इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश के द्वारा और उसमें रिकार्ड किए गए कारणों से किसी नगरपालिका अधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी अन्य कर्मचारी, जो परिषद् के कनिष्ठ अभियंता से नीचे की रैंक का न हो, को इस अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत किसी अनधिकृत निर्माण अथवा उससे संबंधित परिसरों को सील करने का निदेश दे सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए आदेश की एक प्रति, इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों को सील करने के तत्काल बाद, अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों के स्वामी अथवा कब्जेदार को सौंप दी जाएगी और उसके स्वामी अथवा कब्जेदार के स्थल पर मौजूद न होने की स्थिति में उक्त प्रति उक्त अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों के किसी स्पष्ट/प्रमुख स्थान पर चिपकायी जाए।

(3) अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों का स्वामी अथवा कब्जेदार, जिसका अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर, जैसा भी मामला हो, उप-नियम (1) के अन्तर्गत सील किया गया हो, अध्यक्ष अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस प्रकार के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।

(4) अनधिकृत निर्माण को सील किए जाने से पूर्व नगर पालिका अधिकारी अथवा उप-नियम (1) में उल्लिखित अन्य नगर पालिका कर्मचारी अनुमानित मापों सहित उस अनधिकृत निर्माण का

एक रेखाचित्र अथवा नक्शा तैयार करेगा।

(5) नगर पालिका अधिकारी अथवा उप-नियम (1) में उल्लिखित अन्य नगर पालिका कर्मचारी, यह सुनिश्चित करने के पश्चात्, कि अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों के अन्य निकास मार्गों और प्रवेश मार्गों पर ताला लगा दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है अथवा उनकी तार, रस्सी अथवा जाली वाले तार (वायर-मेश) से घेराबंदी कर दी गई है, उस भवन, जिसमें अनधिकृत निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है, के बाहरी दरवाजे अथवा निकास मार्ग को सील कर सकता है और जहां इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों की तार, रस्सी अथवा जाली वाले तार (वायर-मेश) से अथवा अन्य किसी सामग्री से घेराबंदी की जा सकती हो अथवा उसकी कोई चारदीवारी न हो जिससे उसकी सीलिंग करना कठिन हो तो छेड़खानी अथवा हस्तक्षेप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उक्त नगर पालिका अधिकारी अथवा अन्य नगर पालिका कर्मचारी निगरानी के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति की तैनाती सहित अन्य कोई ऐसा तरीका अपना सकता है जिससे कोई व्यक्ति उप-नियम (1) के अंतर्गत लगाई गई सील को तोड़े अथवा हटाए बिना अनधिकृत निर्माण अथवा परिसरों में प्रवेश न कर सके अथवा उसे खोल न सके।

(6) जहां कोई अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर, जिसे इस नियम के अंतर्गत सील किए जाने का आदेश दिया गया हो, पर ताला लगा अथवा अगम्य पाया जाए तो नगरपालिका अधिकारी अथवा नगर पालिका का अन्य कर्मचारी जिसे अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को सील करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या तो ताले को तोड़कर खुलवा अथवा खोल अथवा तोड़ सकता है अथवा किसी दरवाजे, गेट अथवा किसी अन्य अवरोधक को खोल अथवा खुलवा सकता है और उस अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर में प्रवेश कर सकता है जिसमें अनधिकृत निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर अन्दर से सुरक्षित है और तत्पश्चात् अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर, जैसा भी मामला हो, में ताला लगा सकता है तथा उसे सील कर सकता है :

बशर्ते कि जहां किसी अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को खोलना अनिवार्य हो, तो परिसर में अथवा अनधिकृत निर्माण वाले स्थल पर पाई गई वस्तुओं अथवा सामग्री की एक सूची दो गवाहों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी और इसकी एक प्रति उस स्थल पर मौजूद मालिक अथवा कब्जेदार को सौंपी जाएगी।

(7) इस नियम में संदर्भित अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को नई दिल्ली नगर परिषद् की मोहर लगाकर सील किया जाएगा, जो अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा।

(8) नगर परिषद् का वह अधिकारी अथवा नगर परिषद् का कोई अन्य कर्मचारी जिसे अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को सील करने को निर्देश दिया गया है, इस नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को सील कर दिए जाने के बाद लिखित रूप में इनको सूचित करेगा—

- (क) उस क्षेत्र के थाने में जहां अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर स्थित है; अथवा
- (ख) कोई अन्य थाना जिसे इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया हो; और
- (ग) वह अधिकारी जिसके निर्देशों के आधार पर अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को सील किया गया है।

4. **परिसर अथवा अनधिकृत निर्माण की सील के साथ छेड़छाड़.**—यदि किसी व्यक्ति, नगर परिषद् अधिकारी अथवा नगर परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी, जिसे अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर को सील करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो अथवा न किया गया हो, को यह पता चलता है कि अनधिकृत निर्माण अथवा परिसर जैसा भी मामला हो पर इन नियमों के अंतर्गत लगाई गई सील टूटी हुई है अथवा इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वह तत्काल संबंधित थाने में इसकी लिखित रिपोर्ट करेगा।

5. **निरस्त करना तथा व्यावृत्ति.**—(1) नई दिल्ली नगर समिति (अप्राधिकृत निर्माणों की सीलिंग) नियमावली, 1986 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समान प्रावधानों के अंतर्गत किया गया अथवा की गई समझी जाएगी।

[फा.सं. यू. 14011/129/2006-दिल्ली-II]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2008

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 250 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the New Delhi Municipal Council (Sealing of Unauthorised Construction) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);
- (b) “Council” means the New Delhi Municipal Council established under the Act;
- (c) “unauthorised construction” means the erection of any building or execution of any work which has been commenced, or is being carried on, or has been completed without or contrary to the sanction referred to in Section 241 of the Act or in contravention of any condition subject to

which such sanction was accorded or in contravention of any of the provisions of the Act or bye-laws made thereunder.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of sealing of unauthorised constructions.—(1) The Chairperson or an officer authorised by him in this behalf under Section 400 of the Act, may, by order and for reasons recorded therein, direct any municipal officer or any other municipal employee not below the rank of a Junior Engineer of the Council to seal any unauthorised construction or premises relating thereto under Section 250 of the Act.

(2) A copy of the order made under sub-rule (1) shall be delivered to the owner or occupier of the unauthorised construction or premises immediately after the sealing of such unauthorised construction or premises and in case the owner or the occupier is not available at the site, the said copy may be pasted at some conspicuous place of the said unauthorised construction or premises.

(3) The owner or occupier of the unauthorised construction or the premises whose unauthorised construction or premises, as the case may be, has been sealed under sub-rule (1), may obtain a certified copy of such order from the Chairperson or the officer authorised by him in this behalf.

(4) The municipal officer or other municipal employee referred to in sub-rule (1) may, before the sealing of the unauthorised construction, prepare a rough sketch or plan of the unauthorised construction along with approximate measurements.

(5) The municipal officer or other municipal employee referred to in sub-rule (1), may seal the outer door or the opening of the building in which the unauthorised construction has been, or is being, made after ensuring that other outlets and inlets of the unauthorised construction or the premises have been properly locked, bolted or encircled with wire, rope or wire-mesh or any other material and where such unauthorised construction or premises cannot be enclosed with wire, rope or wire-mesh or any other material or has no boundary walls making the sealing thereof difficult, the municipal officer or the other municipal employee, as aforesaid, shall be authorised to take or adopt any other means including the posting of any person for watch and ward purposes with a view to ensure the same against tampering or interfering in a manner that no person can enter into or open the unauthorised construction or the premises without breaking or removing the seal affixed under sub-rule (1).

(6) Where any unauthorised construction or

premises which has been ordered to be sealed under this rule is found to be locked or inaccessible, the municipal officer or other municipal employee authorised to seal the unauthorised construction or the premises, may, either break open the lock or open or cause to be opened any door, gate or any other barrier and enter the unauthorised construction or the premises where the unauthorised construction has been, or is being, made so as to ensure that the unauthorised construction or the premises is secured from within and then lock and seal the unauthorised construction or the premises, as the case may be:

Provided that where any unauthorised construction or premises is forced open, an inventory of the articles or material found in the premises or on the site of the unauthorised construction shall be prepared in the presence of two witnesses and a copy thereof shall be delivered to the owner or occupier present at the site.

(7) The unauthorised construction or the premises referred to in this rule shall be sealed with the seal of the New Delhi Municipal Council, which shall remain in the custody of an officer authorised by the Chairperson in this behalf.

(8) The municipal officer or any other municipal employee, directed to seal the unauthorised construction or premises, after such unauthorised construction or premises has been sealed in the manner provided in this rule, shall inform in writing to—

- (a) the Police Station of the area in which unauthorised construction or the premises is situated; or
- (b) any other Police Station as may be specified for the purpose in this behalf; and
- (c) the officer on whose directions unauthorised construction or the premises has been sealed.

4. Tampering with seal of premises or unauthorised construction.—If any person, municipal officer or other municipal employee whether authorised to seal the unauthorised construction or the premises or not, finds that the seal as affixed under these rules on the unauthorised construction or the premises, as the case may be, has been broken or tampered with, shall report the matter in writing immediately to the Police Station concerned.

5. Repeal and saving.—(1) The New Delhi Municipal Committee (Sealing of Unauthorised Constructions) Rules, 1986 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[F. No. U. 14011/129/2006-Delhi-II]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.